

हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-

बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210 मो. 9879141480

संपादक : सुरेश मौर्व्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 230, शनिवार, 15 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

जेवर एयरपोर्ट के लिए 3900 किसानों की सहमति, धारा 11 की कार्रवाई जल्द शुरू होने की उम्मीद

ग्रेटर नोएडा। जेवर एयरपोर्ट के लिए अब तक 3900 किसानों ने सहमति दे दी है। एक-दो दिन में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत के पार पहुँच जाएगा। इससे अब धारा 11 की कार्रवाई जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1 सितंबर से प्रभावित परिवारों द्वारा सहमति देने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। कृषक व प्रभावित परिवारों को मिलाकर गुरुवार को करीब 150 किसानों ने सहमति दी है। सहमति देने वालों किसानों का आंकड़ा 3900 के पास पहुँच गया है। 5900 किसान इस परियोजना की जद में आ रहे हैं। 300 प्रभावित परिवारों की और सहमति आने के बाद किसानों का आंकड़ा 70 प्रतिशत के पार पहुँच जाएगा। इसके बाद धारा-11 की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। गुरुवार को जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने गांव नाला फूल खान में रह्तेरा, रोही, नाला शरीफ खानं, नाला छीतर व दयानतपुर के किसानों के साथ बैठक की।

सीएम ने दिया किसानों के बेहतर विस्थापन का भरोसा जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बीते रविवार को दिल्ली स्थित यूपी सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हो रहे किसानों के मुद्दे पर बात की थी। वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रभावित होने वाले किसानों के बेहतर विस्थापन का भरोसा दिया था। जेवर विधायक ने किसानों के उचित व्यवस्थापन और अन्य सुविधाओं पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। विधायक के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की तर्की उनके लिए सर्वोपरि है। किसानों को बेतर विस्थापन और उचित सुविधाएं दी जाएंगी। विधायक ने बताया है कि 320 भूमिहीन परिवारों के साथ करीब 3105 किसानों की सहमति के साथ एयरपोर्ट के लिए जरूरी भूमि में से 86 फीसदी से अधिक जमीन मिलना तय हो गया है। उनके आह्वान पर ग्राम पारोही, रोही, दयानतपुर व बनवारीवास आदि गांवों के लोगों ने अपनी सहमति जिला प्रशासन को दी है।

नर्स और काउंसलर के भरोसे किया जा रहा एड्स रोगियों का इलाज

गाजियाबाद। 1619 एड्स रोगियों का इलाज मात्र एक नर्स और एक काउंसलर के भरोसे चल रहा है। इन रोगियों का इलाज करने के लिए एमएमजी अस्पताल में चल रहे एफआईएआरटी केंद्र में पिछले नौ महीने से कोई चिकित्सक नहीं हैं। ऐसे में पुराने 1619 एड्स रोगियों को दवा देकर केंद्र से लौटा दिया जा रहा है। वहीं नए एड्स रोगियों को मजबूरी में मेरठ भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में करीब 1619 एड्स रोगी हैं। इनका इलाज करने के लिए एमएमजी अस्पताल में एफ आईए आरटी केंद्र है। इस केंद्र पर तैनात चिकित्सक ने इसी साल जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। चिकित्सक के जाने के बाद इस केंद्र को अभी तक कोई नया चिकित्सक नहीं मिला है। इस केंद्र पर वर्तमान में मात्र एक स्टाफ नर्स और एक काउंसलर है, जो कि पुराने ही 1619 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जबकि इलाज के लिए आने वाले नए एड्स रोगियों को चिकित्सक न होने के कारण सही इलाज के लिए मेरठ भेजा जा रहा है। ऐसे में इन रोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं पुराने मरीजों का भी इलाज करने में नर्स और काउंसलर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

चिकित्सक आने को तैयार नहीं : एफ आईए आरटी केंद्र पर चिकित्सक का संविदा का पद है। इस पद का वेतन मात्र 36 हजार रुपये प्रति माह है। इस पद पर एमबीबीएस चिकित्सक को लाने के लिए कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई भी एमबीबीएस चिकित्सक संविदा पर मात्र 36 हजार के वेतन पर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यही वजह है कि तैयार कोशिशों के बाद भी इस केंद्र के लिए कोई चिकित्सक नहीं मिल रहा है। इस कारण यह केंद्र पिछले नौ माह से बिना चिकित्सक के चल रहा है।

बीस से ज्यादा बच्चे भी हैं शामिल एफ आईए आरटी केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक एड्स रोगियों में करीब 20 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। जिनका इलाज किया जा रहा है। इस केंद्र में चिकित्सक की तैनाती के लिए शासन को पत्र कई बार लिखा गया है। चिकित्सक मिलने से बड़ी राहत इस केंद्र की नर्स और काउंसलर को मिलेगी।

दैनिक

क्रांति समय

संपादक : सुरेश मौर्व्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 230, शनिवार, 15 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1



सरकारी व निगम स्कूलों के लिए इस साल पूरी नहीं हो पाएगी 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया

नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी व नगर निगम के स्कूलों के लिए लगभग 15 हजार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल भी पूरी नहीं हो पाएगी। दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने हाईकोर्ट से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए फरवरी, 2019 तक का समय मांगा है। जस्टिस सिद्धार्थ मुख्तार के समक्ष डीएसएसएसबी ने इस बारे में अर्जी दाखिल की है। इसके अनुसार तय समय पर नियुक्ति प्रक्रिया इसलिए पूरी नहीं पाएगी क्योंकि इसके लिए जिस कंपनी से करार हुई थी वह इतने कम समय में आनलाइन परीक्षा पूरी करने में असमर्थ है। पहले नियुक्ति प्रक्रिया अक्तूबर, 2018 तक पूरी होनी थी। डीएसएसएसबी ने हाईकोर्ट में कहा है कि उसने इस बार शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आनलाइन कराने का निर्णय लिया था। साथ ही कहा है कि उसने इसके लिए केंद्रीय मानवसंसाधन मंत्रालय से संबद्ध कंपनी ईडीसीआईएल से आनलाइन परीक्षा कराने का करारा किया और मई 2018 के मध्य से 65 श्रेणी में 15 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षाएं आनलाइन कराने का आग्रह किया। डीएसएसएसबी ने हाईकोर्ट को बताया है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होने और समय कम होने के कारण ईडीसीआईएल सभी 65 श्रेणी में

शिक्षकों के आनलाइन परीक्षाएं पूरी कराने में असमर्थ है। डीएसएसएसबी ने यह जानकारी देते हुए हाईकोर्ट से सरकारी व निगम स्कूलों के लिए 16 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए फरवरी, 2019 तक का वक्त देने की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर, 2017 को गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की डीएसएसएसबी को अक्तूबर, 2018 तक 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।

कुछ श्रेणी में आनलाइन तो कुछ श्रेणी में आफलाइन होगी परीक्षाएं डीएसएसएसबी ने हाईकोर्ट को बताया है कि अब कुछ श्रेणी में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आनलाइन और कुछ में आफलाइन होगी। जिस कंपनी से आनलाइन परीक्षा कराने का करार हुआ है, वह इसे तय समय में करने में असमर्थ है। कुल 65 श्रेणी में लगभग 16 हजार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

अतिथि शिक्षकों को भी मिल सकता है सेवा विस्तार

यदि डीएसएसएसबी तय समय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने में विफल रहती है तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में अध्यापन का काम कर रहे करीब 20 हजार अतिथि शिक्षकों को सेवा विस्तार मिल सकता है।

तीन मुठभेड़ों मे आठ आतंकियों को ढेर किया, 12 जवान जख्मी

श्रीनगर, एजेंसी। सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को तीन अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में आठ आतंकियों को मार गिराया। जम्मू के काकरियाल में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी ढेर हुए। 12 जवान जख्मी हुए। मुठभेड़ के पहले आतंकी रेयासी में एक घर में घुसे थे। यहां उन्होंने बिस्किट और सेब मांगकर खाए थे। वहीं, बीएसएफ ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तीन और बारामूला के सोपोर और रियासी में सुरक्षाबलों ने दो-दो आतंकियों को मार गिराया।

काकरियाल मुठभेड़: मेजर जनरल अरविंद भाटिया ने बताया कि ट्रक पर सवार तीन आतंकियों ने बुधवार को उधमपुर के झज्जर-कोटली चेकपोस्ट पर हमला कर दिया था। इसमें एक सीआरपीएफ जवान और फॉरेस्ट गार्ड जख्मी हुआ था। सुरक्षाबलों ने बुधवार को ही आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आतंकियों ने हाल ही में सांबा, बोबियां अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी। इनकी मदद एक ट्रक ड्राइवर ने की थी। पुलिस ने वह ट्रक बरामद कर लिया है, जिससे आतंकी रेयासी तक आए थे।

सोपोर में मुठभेड़: पुलिस के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद गुरुवार सुबह सोपोर के चिकीपोरा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उसी दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि मारे गए आतंकियों के शव सीमा बड़ के निकट हैं व उन्हें अब तक बरामद नहीं किया गया है। उधर, इलाके की अब भी तलाशी ली जा रही है। दो आतंकवादी सोपोर के अरमपोर इलाके में मारे गए।

काकरियाल सोपोर और केरन सेक्टर में हुई मुठभेड़

आतंकी गिरफ्तार, गणेश वतुर्थी पर यूपी को दहलाने की थी साजिश

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के सदसिध आतंकी को गिरफ्तार किया है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि गिरफ्तार आतंकी गणेश वतुर्थी पर हमले करने वाला था। वो भारतीय नागरिक है और पढ़ा-लिखा है। स्वाल-जवाब के दौरान उसने ये बात कबूल की है कि वो साल 2017 में वो कश्मीर के किश्तवाड में ट्रेनिंग लेने गया था। हिजबुल के आतंकी का नाम कमरउजजमा बताया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी असम के नौगंव का रहने वाला है। वो काफी दिनों से कानपुर में रेकी कर रहा था। एटीएस को उसके फोन से रेकी के कई वीडियो भी मिले हैं। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि वयौंकि आतंकी भारत का ही रहने वाला है इसलिए संगठन इस आगे बढ़ा रही थी। भारतीय होने की वजह से उस पर किसी को शक भी नहीं होता। बता दें कि हिजबुल मुजाहिद्दीन एक अलगाववादी आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन को मुहम्मद एहसान डार ने किया था। जम्मू-कश्मीर में ये संगठन काफी सक्रिय है।

दहेज कानून में गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता (आपीसी) की धारा 498ए के तहत दहेज प्रताड़ना केस में सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के डीजीपी को इस मुद्दे पर पुलिस अप्सरों व कर्मियों में जागरूकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धान्त दिया है वो क्या है। इसके साथ ही, गिरफ्तारी से पहले दहेज प्रताड़ना की जांच के लिए सिविल सोसायटी की कमेटी बनाने की गाइडलाइन को हटया गया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पति और उसके रिश्तेदारों के संरक्षण करने के लिए जमानत के रूप में अदालत के पास

अधिकार मौजूद है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस तरह आपराधिक मामले की जांच के लिए सिविल कमेटी नियुक्त नहीं कर सकता, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय बेंच के फैसले को संशोधित करते हुए तीन सदस्यी बेंच ने कहा कि इस तरह कोर्ट कानून की खामियों को नहीं भर सकता। ये कार्यपालिका द्वारा कानून लाकर ही करना संभव है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सर्वोच्च अदालत ने दोहराया कि अगर दोनों पक्षों में समझौता होता है तो कानून के मुताबिक वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर पति पक्ष कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करता है तो केस की उसी

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दे दिया है।

दिन सुनवाई की जा सकती है। इससे पहले, इसी साल अप्रैल माह में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2017 में इस मामले में चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत गिरफ्तारी न हो और ऐसे मामलों को देखने के लिए हर जिले में फैमिली वेलफेयर कमिटी बनाया जाए। साथ ही, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई हो।

दो जजों की बेंच के आदेश को ही

RNI.No.: GUJHIN/2018/75100

हमारे यहां पर एल.आई. सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-

बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत -394210 मो. 8980974047

E-mail: krantisamay@gmail.com

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

मयूर विहार में 10 साल की मासूम से रेप, सड़क पर मिली खून से लथपथ

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 3 में गुरुवार रात स्मृति वन पार्क के पास एक 10 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने बच्ची पर जानलेवा हमला किया। बच्ची खून से लथपथ और बेहोश मिली। बच्ची को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसे एम्स में रेफर कर दिया गया उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय बच्ची परिवार के साथ गाजीपुर इलाके में रहती है। गुरुवार रात आरोपी युवक ने उस बच्ची के साथ दरिन्दगी को अंजाम दिया है। रात करीब 8:30 बजे पुलिस को स्मृति वन पार्क के सामने बच्ची के खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में होने की सूचना मिली। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। बच्ची को लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की कोशिश की थी पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

राजनाथ सिंह की सख्ती के बाद गिरफ्तार हुआ लड़की को पीटने वाला पुलिसकर्मी का बेटा

का एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से फोन पर इस बारे में बात की है और इस पर उचित कारवाई करने के लिए कहा है। वीडियो में तोमर महिला को घसीटते हुए और उसे बुरी तरह पीटते हुए दिख रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक अन्य युवती से भी शिकायत मिली है। उसने आरोप लगाया है कि उसके पुरुष मित्र तोमर ने उसे यह वीडियो दिखाया, जिसमें वह युवती को पीटते दिख रहा है। साथ ही, आरोपी ने उसे धमकी दी है कि यदि उसने उसकी नहीं सुनी, तो उसका भी यही हथ्र होगा। डीसीपी (पश्चिम) मोनिका भारद्वाज ने बताया कि इसके बाद युवती गुरुवार को पुलिस के पास पहुंची और तोमर के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। **लड़की को पीटने वाले युवक पर सख्त कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस :** **राजनाथ गृहमंत्री ने पुलिस कमिश्नर को दिए कार्रवाई के आदेश** शुक्रवार को जब केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तिलक नगर में एक लड़की की एक युवक द्वारा बेरहमी से पिटाई का वीडियो देखकर पुलिस आयुक्त से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा, तब दिल्ली पुलिस हकत में आई

और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'एक लड़की को एक युवक द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। मैंने @DelhiPolice कमिश्नर से फोन पर इस बारे में बात की है और इस पर उचित कारवाई करने के लिए कहा है।'डीसीपी (द्वारका) एंटो अल्फोंस के अनुसार, लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपी रोहित तोमर ने उसे उत्तम नगर में अपने दोस्त के ऑफिस में बुलाया था तथा उसका यौन शोषण किया। डीसीपी ने बताया कि लड़की ने आरोप लगाया है कि जब उसने कहा कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी तो आरोपी ने उसे पीटना शुरू कर दिया।

अल्फोंस ने बताया कि यह घटना दो सितंबर को उत्तम नगर में हुई। एक महिला से एक अन्य शिकायत मिली है कि उसके दोस्त तोमर ने उसे वह वीडियो दिखाई और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे भी ऐसे ही नतीजे भुगतने पड़ेंगे। डीसीपी (पश्चिम) मोनिका भारद्वाज ने कहा कि इसके बाद महिला गुरुवार को पुलिस के पास पहुंची और तोमर के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

गुरुग्राम : मंडलायुक्त ने दिए कथित मरिजद से सील हटाने के आदेश

गुरुग्राम। मंडलायुक्त डॉ. सुरेश ने गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में स्थित एक कथित मस्जिद पर लगी नगर निगम की सील को हटाने के आदेश दिए हैं। यह सील निगम की टीम द्वारा शाम चार बजे तक हटाई जा सकती है। मंडलायुक्त ने यह आदेश उपायुक्त विनय प्रताप सिंह से पूरे मामले को समझने और दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद दिए हैं। मुस्लिम संगठनों ने मंडलायुक्त के इस फैसले का स्वागत किया है। इधर, मामले की जानकारी हिन्दू संगठनों को मिलने के बाद एक बार फिर नए सिर से गहमा-गहमी शुरू हो गई है।

हिन्दू संगठनों की ओर से कोई भी सामने नहीं आया है। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे बेरी वाला बाग में धरने पर बैठे हिन्दू संगठन के लोगों को बलपूर्वक भगा दिया था।

आत्मदाह की चेतावनी के साथ अनशन कर रहे यति नरसिम्हा नंद सरस्वती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी प्रकार दोपहर में एसडीएम संजीव सिंगला की मौजूदगी में पुलिस ने मस्जिद के सामने धरने पर बैठे मुस्लिम संगठन के लोगों को भी भगा दिया और उनके टेंट-तंबू जब्त कर लिए थे।

आपस में भिड़े हिन्दू संगठन के लोग

यति नरसिम्हानन्द सरस्वती की गिरफ्तारी और मस्जिद के विरोध में शुक्रवार दोपहर माता मंदिर में जुटे हिन्दू संगठन के लोग आपस में ही लड़ पड़े। इन लोगों के बीच विवाद मीडिया में बाइट देने को लेकर

हुआ। हालांकि, थोड़ी देर बार संगठन के ही दूसरे लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया।

मौके पर तनाव कायम

मंडलायुक्त के आदेश से शाम चार बजे तक मस्जिद की सील खुलनी है। चूँकि, जुमे की नमाज इससे पहले होनी है, इसलिए एक तरफ मुस्लिम संगठन के लोग मस्जिद के पास जुटने लगे हैं। वहीं, दूसरी तरफ हिन्दू क्रांति दल के सदस्यों ने भी विरोध करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

पुलिस की इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक, इस संगठन के लोगों ने किसी कीमत पर सील नहीं खुलने देने का निर्णय लिया है। इसके लिए इनकी गोपनीय बैठक चल रही है। हालात को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मलिक और जय सिंह के नेतृत्व में मौके पर तीन थानों की पुलिस के अलावा भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

मस्जिद वाली गली पर पुलिस का कब्जा

पुलिस ने मस्जिद वाली गली पर सुबह से ही कब्जा जमा रखा है। इस गली में जो लोग पहले चले गए, उन्हें छोड़ किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, भले ही वह उस गली में रहने वाले ही क्यों न हों। इसके लिए गली के नुकड़ पर ही एक इम्पेक्टर के नेतृत्व में आठ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसी प्रकार सौ मीटर लंबी गली के अंदर 150 से अधिक पुलिस कर्मी तीन जगह बैरिकेड लगाकर मोर्चा संभाले हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका दायर कर कहा गया कि कोर्ट को कानून में इस तरह का बदलाव करने का हक नहीं है। कानून का मकसद महिलाओं को इंसाफ दिलाना है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते देश भर में दहेज उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी बंद हो गई।

2017 में सुप्रीम के दो जजों की बेंच ने लगाई थी रोक

इससे पहले, जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोगल और जस्टिस यूयू ललित की दो जजों की बेंच ने महिलाओं के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग के मामले को लेकर अहम निर्देश जारी किए थे।

अपने आदेश में कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए ऐसे मामलों में

तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

इसके अनुसार दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब पति या ससुराल वालों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। दहेज प्रताड़ना यानी आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए इस सिलसिले में कुछ दिशा-निर्देश जारी भी किए थे।

दहेज कानून के दुरुपयोग के कई मामले आए सामने

एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 2009 के दौरान करीब 1 लाख 74 हजार लोगों की गिरफ्तारी 498ए के अंतर्गत हुई थी और इनमें 8,352 केस फर्जी साबित हुए।

2012 में 498ए के तहत केस दर्ज करने का रेट 93.6फीसदी रहा जबकि इसमें सिर्फ 14.3 फीसदी ही दोषी ठहराए गए थे।

» प्रसंग



भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में दो दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई ऐसी बातें सामने आईं, जो आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से विपक्ष की गोलबंदी को खारिज करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जो कोशिश की है, उसके परिणाम निःसंदेह आने वाले चुनाव में मिलेंगे।

भाजपा की कार्यकारिणी के निहितार्थ

भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में दो दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई ऐसी बातें सामने आईं, जो आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। गौरतलब है कि यह बैठक 18 और 19 अगस्त को प्रस्तावित थी, किंतु अटलजी के निधन के बाद इसे टाल दिया गया था। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आठ तथा नौ सितंबर को हुई भाजपा की इस कार्यकारिणी को 2019 के लोकसभा चुनाव की जरूरी बैठकों में से प्रमुख माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में भाजपा ने आगामी चुनाव की रणनीति, नेतृत्व और प्रमुख मुद्दों का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया है। इस बैठक में भाजपा ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और लोकसभा तथा तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर मंथन किया। इस मंथन का निचोड़ क्या निकला तथा आने वाले समय में इसका क्या असर होगा यह समझना जरूरी है। जाहिर है कि बैठक में भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में 2022 तक 'नए भारत' के लक्ष्य को हासिल करने की बात की है। इस प्रस्ताव को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया। इस राजनीतिक प्रस्ताव में साल 2022 तक भारत को भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त, भुखमरी तथा संप्रदायवाद से मुक्त भारत का विजन रखा गया है। जाहिर है कि नए भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, जिसको साकार करने की दिशा में सरकार, संगठन को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत का भरोसा देते हुए 2014 के चुनाव से ज्यादा जनसमर्थन हासिल करने का लक्ष्य रखा तथा संगठन को आगामी चुनाव के लिए कमर कसने की सलाह दी। शाह ने विपक्ष द्वारा बनाए जा रहे महगठबंधन को झूठ पर आधारित गठबंधन बताया। कांग्रेस पर हमला करते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि जहां भाजपा 'मैकिंग इंडिया' पर काम कर रही है, तो कांग्रेस 'ब्रेकिंग इंडिया' में लगी हुई है। बहरहाल, एक और सबसे प्रमुख बात अमित शाह ने कही जो आने वाले चुनाव के लिए भाजपा के आत्मविश्वास को दर्शाता है। शाह ने कहा कि आगामी पचास वर्षों तक हमें कोई नहीं हरा सकता। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या भाजपा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अगुआई में वह जमीन तैयार करने लगी है, जिससे भाजपा लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहे। इस कार्यकारिणी में भाजपा ने यह तय किया कि पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

में ही आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इन सब के बीच कार्यकारिणी में भाजपा ने अपना सांगठनिक चुनाव भी टाल दिया है और अमित शाह की अगुआई में ही आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सवाल यह उठता है कि अमित शाह भाजपा के लिए जरूरी क्यों हैं? अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने भाजपा को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता व अमित शाह की संगठन संचालन की कुशलता का जो मेल है, वह भाजपा की चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम कर रही है। यही कारण है कि विगत चार साल व चार माह में संगठन और सरकार बीच में कोई विरोधाभास नजर नहीं आया है।

अमित शाह भाजपा के लिए कितने अहम और कारगर हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। संगठन और विचारधारा के विस्तार में शाह ने जिस योजना के साथ कार्य किया है वह अभूतपूर्व है। यही कारण है उनकी गिनती भाजपा के सबसे सफलतम अध्यक्षों में होती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि जिस राजनीतिक चतुराई के साथ शाह काम करते हैं, उससे उनके सियासी विरोधी प्रायः चित नजर आते हैं। अगर यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी और शाह आज की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। संगठन को आगे बढ़ाने में शाह और सरकार के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी इतने परिपक्व ढंग से राजनीति कर रहे हैं कि विरोधी दलों के पास इस जोड़ी की कोई काट नजर नहीं आ रही है। उसी का परिणाम है कि भिन्न-भिन्न विचारधारा की पार्टियां अपने सिद्धांतों को ताक पर रखकर इनके खिलाफ लामबंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसे भाजपा सहर्ष अपनी सफलता बता रही है। इस जोड़ी की अगर सफलता की बात जब की जा रही है, तो इसके तथ्यों को भी समझना जरूरी है।

2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह को संगठन की कमान सौंपी गई, तब पार्टी केवल सात राज्यों तक सिमटी थी। संगठन का विस्तार भी एक क्षेत्र विशेष में सीमित था। यही कारण था कि भाजपा विरोधी इन्हें हिंदी बेल्ट की पार्टी बोलकर चिढ़ाते थे, लेकिन इस जोड़ी ने इस तिलिस्म को तोड़ा और उन राज्यों में जहां भाजपा की पहुंच नहीं थी वहां न केवल संगठन का विस्तार किया बल्कि कम समय में ही अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया कि वहां भाजपा सरकार बनाने में सफल रही। पूर्वोत्तर के राज्य मसलन मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा और असम में भाजपा को मिली जीत

अमित शाह और मोदी की कुशल रणनीति की सफलता का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। आज भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ 19 राज्यों में सरकार चला रही है। देश के तीन चौथाई भूभाग पर भाजपा का परचम लहरा रहा है। संगठन के स्तर पर बात करें तो जिस भाजपा के पास केवल तीन करोड़ सदस्य होते थे, आज सदस्यों की संख्या ग्यारह करोड़ को पार जा चुकी है। फिर भी अमित शाह इससे संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। जाहिर है उनकी नजर अब दक्षिण भारत के उन राज्यों पर है, जहां पार्टी सत्ता से दूर है। भाजपा कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से कोई चुनौती नहीं है। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर वार किया और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। समापन भाषण में नरेंद्र मोदी 'अजेय भारत, अटल भाजपा' का नारा भी दिया। भाजपा की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो निचोड़ सामने आया है उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भाजपा सरकार के कार्यों, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति तथा प्रत्येक बुद्ध को जीतने के लक्ष्य के साथ आगामी लोकसभा तथा तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जनता के बीच जाएगी।

कुल मिलाकर, आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा पूरी तरह कमर कसकर तैयार है। भाजपा सामाजिक न्याय पर अपनी उपलब्धियों को प्रचारित कर रही है इसीलिए पार्टी ने कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में नए बने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर बुलाई थी। भाजपा एससी एक्ट एक्ट में बदलाव और पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। हालांकि देश के कई हिस्सों में सवर्णों की नाराजगी भी उसके लिए परेशानी का सबब है। राजनीतिक हल्कों में इस मुद्दे को भाजपा के लिए संकटग्रस्त बताया जा रहा है। चुनाव के समय भाजपा इस मुद्दे से कैसे निपटेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इस कार्यकारिणी का एक महत्वपूर्ण संदेश रहा अभी से विधानसभा चुनावों के साथ अगले लोकसभा चुनाव के लिए काम करना। पार्टी ने तय किया कि जिन सीटों पर भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं की थी, वहां अभी से कार्यकर्ताओं की टीम काम करेगी। कार्यकारिणी के पूरे निष्कर्षों को देखें, तो भाजपा आत्मविश्वास से भरी है।

■ **अदिति तिवारी**
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

» राज-विचार

भ्रष्टाचार के प्रति दिखा कड़ा रुख

नए भ्रष्टाचार निरोधक कानून को और भी सख्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचारियों पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। पर जरूरत उस इच्छा शक्ति की भी है, जो अब तक असर नहीं दिखा पाई है।



भारत में भ्रष्टाचार गंभीर समस्या बना हुआ है। आज जनता के बीच आम धारणा यही है कि सरकारी महकमों में कोई भी काम बिना पैसे नहीं होता, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। नए भ्रष्टाचार निरोधक कानून को और सख्त बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचारियों पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। इस कानून को सख्त बनाना इसलिए भी जरूरी था कि भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले लोग नए विकल्प और रास्ते खोज लेते हैं और कमजोर कानून का फायदा उठाते हैं। इससे यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि घूस के एवज में सिर्फ रुपयों की ही मांग की जाती हो। किसी काम को गैरकानूनी रूप से कराने के बदले तमाम तरह के अनुचित लाभ लेना और देना भी भ्रष्टाचार का जरिया बना हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम 2018 में साफ कहा गया है कि यौन तुष्टि की मांग करने और स्वीकार करने को भी अब घूस लेना माना जाएगा। इस नए प्रवधान के तहत अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ऐसे अनेक मामले सामने आते रहे हैं जिनमें बतौर रिश्तत यौन तुष्टि की मांग की गई थी।

दरअसल, भ्रष्टाचार निरोधक कानून में दिक्कत यह थी कि इसमें 'अनुचित' लाभ या वित्तीय लाभ की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। लेकिन फरवरी 2015 में विधि आयोग ने अपना सुझाव देते हुए 'अनुचित' लाभ की जो व्याख्या की, उससे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा और कसा है। संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक कानून इसी साल जुलाई में नए और सख्त रूप में अमल में आया है। ऐसी देरों शिकायतें आती रही हैं कि घूस के बदले अधिकारी और कर्मचारी रुपयों के बजाय दूसरे लाभ की मांग करते हैं। इनमें यौन तुष्टि की मांग के अलावा विदेश यात्रा का बंदोबस्त, हवाई टिकट और होटलों का इंतजाम, महंगे उपहारों की मांग के अलावा किसी तीसरे पक्ष के जरिए चल-अचल संपत्ति खरीदने में नगदी का भुगतान, क्लब की सदस्यता हासिल करना, अपने परिवार के किसी सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त के लिए या फिर इनकी आड़ में कुछ लाभ प्राप्त करना भी है।

यह सर्वविदित है कि आम लोगों के लिए सरकारी दफ्तरों में जायज काम कराना भी आसान नहीं है। इतना ही नहीं, नौकरी, इंटरव्यू, स्कूल-कॉलेजों में दाखिले, अस्पताल में इलाज, गरीबों के लिए चलने वाली योजनाएं तक भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त हैं। आज जिस तेजी से इस तरह के मामले बढ़े हैं, उनसे निपटने में तीन दशक पुराना कानून बेअसर साबित हो रहा था। संशोधित कानून में मुख्य बात यह भी है कि अब घूस लेने वाले ही नहीं, बल्कि देने वाले को भी इसकी जद में लाया गया है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है उस पर कारगर तरीके से अमल करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति, जो कि ज्यादातर मामलों में देखने में नहीं आती है।

हिन्दी सनातनकाल से सर्वव्यापी और सर्वग्राह्य रही है। कुछ मॉडल विचारणीय हैं: आठ सौ साल पहले अमीर खुसरो ने अपने उस्ताद हजरत निजामुद्दीन औलिया के निधन पर अपनी शोककुल भावना को हिन्दी में व्यक्त किया जबकि उनकी मातृभाषा फारसी थी:

*खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग।
तन मेरो, मन पीउ को, दोउ भये इकरंग।
गोरी सोवे सेज पे, मुख पर डोउ केस।
चल खुसरो घर आपनै, रैन भई चहुं देस।*

जाने माने कवि टीएस इलियट को वेस्टलैंड शीर्षक जिस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला उसकी अंतिम पंक्ति थी ऊँ शांति शांति शांति। सन् 1945 में अमेरिका के प्रथम एटमबम के विस्फोट-दृश्य को सूत्ररूपेण व्यक्त करने के लिए जो शब्द मिले वे थे सूर्यकोटि समप्रभः।

राष्ट्रभाषा बनने के लिए हिन्दी किसी सरकारी घोषणा की मोहताज नहीं है। क्या सहस्राब्दियों पूर्व जन्मे शंकर (686-722 ई.) को किसी सरकार ने आदि शंकराचार्य बनाया था? क्या नरेंद्रनाथ (1863-1902) को स्वामी विवेकानंद की पदवी सरकार ने दी थी? क्या मदनमोहन मालवीय (1861-1946) को महामना की उपाधि सरकार-प्रदत्त थी? और क्या मोहनदास करमचंद गांधी (1869-1948) का महात्मा जैसा लोक-संबोधन किसी सरकार के रहमो-कसम का मोहताज था? ये सभी संबोधन महामानवों को एक कृतज्ञ-राष्ट्र के सार्वजनिक प्रणाम का प्रतीक थे। तब फिर सवा सौ करोड़ भारतवासियों और करोड़ों प्रवासी-भारतीयों की भाषा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किसी सरकार की क्या जरूरत है? जैसे कुछ शक्तिशाली लोकवासी होकर भी लोकोत्तर हो जाती हैं वैसे ही हिन्दी भी मात्र भाषा न होकर हमारी अस्मिता उपलब्धि का अभिज्ञान है।

भाषाएं, सरकार नहीं बनाया करती। उन्हें लोग बनाते हैं। लोक बनाता है। इन्हीं अर्थ-संदर्भों में हिन्दी हमारी लोकभाषा है। वह तो राष्ट्र के स्वरुपाव की सहज अभिव्यक्ति है। वह तो हमारे लिए जीवन-वेद है। आसेतु-हिमालय जिसे बोलता और समझा जाता हो वह यदि हमारा वाक-तंत्रिकाग्रंथ नहीं है तो और क्या है? जहां तक सरकार का प्रश्न है संसदीय-स्तर पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा न होकर अंग्रेजी और कुछ प्रादेशिक भाषाओं सहित हमारी राजभाषा है। भाषा-बहुल भारत की लगभग सभी प्रादेशिक भाषाएँ हिन्दी की ही भाँति संस्कृत-जन्मा होने के कारण उसकी अनुज्ञा-सहोदरा हैं। हमारे लोक व हमारी लोकभाषा की वाक-संस्कृति में भाषाओं को पचाकर अपना



हिंदी जब हिन्दी दिवस, सप्ताह और पखवाड़ों तक सिमटकर रह गई है, तो उसकी दुर्दशा को समझना भी बहुत कठिन नहीं है। हमने भारतीय भाषाओं को पीछे छोड़कर अंग्रेजी को अपने सिर पर लाद लिया है और यह वह काम है, जो लार्ड मैकाले ने कम, हमारे अपनों ने ज्यादा कराया है। ऐसे में हिन्दी को सिर्फ युवा पीढ़ी से ही उम्मीद है मगर वह भी हिंग्लिश में फंसा है।

बना लेने की क्षमता के दृष्टिगत अंग्रेजी हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तमाम धर्मों और संस्कृतियों की भाँति हम अंग्रेजी को पचा चुके हैं। हमारी झाड़ू-पोछे वाली बाइयों ने अपने शराबी पतियों के कारण टेन्सन (टेंशन) शब्द को आम-फहम बना लिया है। यदि किसी दिन आपके घर में ज्यादा बर्तन निकलें तो बरतन मांजने वाली बाई तुरंत 'एक्स्ट्रा पैमेंट' मांगने लगती है। हम अंग्रेजी अपने लंबो-लहजे से बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप मध्यप्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में हैं। वहां का एक सामान्य नागरिक शिकायत करता है कि हम रोज सुबह-शाम जजेज-कोर्ट (अदालत) जाते हैं लेकिन जज नहीं मिलता। अब क्या अपने प्राण दे दें? हम बघेलखंडी इसी बात को अपनी अंग्रेजी मिश्रित शैली में कुछ इस तरह कहेंगे- मोरिंगऊ का अईत है। इवंगिंगऊ का जइत है। जजजी गे रहे। सार जजजवा नई मिला। अबका आपन ज्यू दै देइ? सभी प्रांतों ने अंग्रेजी को अपनी-अपनी भाषाओं की सहचरी बनाकर तमिलियन-अंग्रेजी, बंगाली-अंग्रेजी और भोजपुरी-अंग्रेजी बना दिया है। उसका भारतीकरण हो चुका है। हिन्दी को राजपथ का आसरा नहीं चाहिए। वह जनपथ पर सर्वव्यापी है। उसे अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषाओं को लेकर कोई चिंता नहीं है। किंतु हिन्दी को स्वयं

हिन्दी-भाषियों से चिंता होना चाहिए। हमने त्रिभाषा-फार्मूला नहीं अपनाया जिसमें हिन्दी-अंग्रेजी के अलावा एक प्रादेशिक भाषा सीखने का सुझाव था। हमारे देश की ही प्रादेशिक भाषों के प्रति हमारा जो व्यवहार है उनकी प्रतिक्रिया भी हमारे प्रति वैसी ही तो होगी। हमारे देश में एक नवधनाढ्य मध्यमवर्ग अपनी अधिकचरी अंग्रेजी को स्टेट्स सिम्बल मान बैठा है। वह अपने बच्चों को इंग्लिश-मीडियम स्कूलों में भारी फीस देकर भरती करने के लिए तीन बजे रात से क्यू में खड़ा रहता है। हमारे तिरसठ-चैंसठ से अनभिज्ञ बच्चे सिक्स्टी थी और सिक्स्टी फोर बोलते हैं। हमारी ग्लूबलिस्मयां ग्रीन टी का सेवन करके ठेके वाले से फ्रेश वैजिटेबल देने का आग्रह करती हैं। भोपाल स्थित अटल बिहारी विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम के तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु विद्यार्थी नहीं मिलते। सही या गलत हमारी नौजवान पीढ़ी के मन में यह बात तो बैठ गई है कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा के बिना स्वदेश में भी जीविका के साधन या नौकरी मिलना मुश्किल है। आज के भूमंडलीकृत बाजारक विश्वग्राम के निवासी विश्वगुरुओं को अपने गुरुत्वाकर्षण हेतु नई कसौटी खोजनी होगी। सवाल हमारी भावी पीढ़ी का है। बोलचाल की हिन्दी में अंग्रेजी सहित अन्य

भाषाओं-बोलियों के शब्द आना स्वाभाविक है। किंतु लिखित हिन्दी में जानबूझकर अंग्रेजी शब्दों के थिंगुड़े लगाना चिंता पैदा करता है। हमारा प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस भाषाई-अपसंस्कृति को इरादतन प्रोत्साहन दे रहा है। मिसाल के तौर पर एक प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक का एक शीर्षक देखें: 'कैरेक्टर-बेस्ड थियर लुक विमेन च्वाइस।' 'क्या चरित्र-आधारित केश विन्यास महिलाओं की पसंद' लिखना आम आदमी की समझ में नहीं आता? कुछ दिनों पहले भोपाल के कुछ प्रबुद्ध हिन्दीसेवियों ने एक बैठक करके तय किया कि मीडिया में जो हिंग्लिश चल रही है उसके प्रति चिंता सर्वसंबंधितों को व्यक्त की जाए। एक अतिउत्साही हिन्दी भक्त ने तो यहां तक कह दिया कि जो अखबार ऐसी भाषा लिखते हैं उन्हें न खरीदें। हम स्वयं से पूछें कि क्या इस दिशा में वास्तव में हमने कोई सकारात्मक पहल की? भाषा को साजिशन भ्रष्ट करने के सुनियोजित प्रयास को जाबुआ फ़िरामैन ने भाषा के क्रियोलाइजेशन की संज्ञा दी। जो हिन्दी भक्त मंशिराल को हिन्दी की वैकल्पिक राजधानी मानकर विश्व हिन्दी सम्मेलनों में फोटो-ऑफ़ करते हैं, वे क्रियोल शब्द से भली भाँति परिचित होंगे। वहां फ़्रांसीसियों और स्थानीयों का रक्त मिश्रण हुआ है। इसी प्रकार फ़्रेंच-अंग्रेजी और स्थानीय भाषा से उत्पन्न वर्णसंकर भाषा को क्रियोल कहते हैं। हमारे देश में हिंग्लिश यही कर रही है। रही-सही कमी वोट बैंक के चक्कर में राजनीति ने पूरी कर दी। हिन्दी भाषियों के संख्या बल को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं।

17वीं सदी में मराठीभाषी शिवाजी और कविवर भूषण की वार्ता इस प्रसंग में मननीय है। भूषण ने शिवाजी से कहा कि मैं मराठी सीखकर आपका जीवन चरित्र लिखना चाहता हूं। शिवाजी ने अनुरोध किया कि मराठी क्यों? हिन्दी में लिखो। इस प्रश्न पर भूषण ने लिखा: शिवराज चरित्र लिख्यो कविवरभूषण के चित्त। भातिभाति भूषित करयो निज भाषा कवित। हिन्दी को कमजोर करना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना है। 14 अगस्त, 1947 तक जो हिन्दी, देश की राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता संग्राम को बढ़ावा देने का साधन हो रहा है, वही 26 जनवरी, 1950 से लागू हमारे संविधान में अंग्रेजी की हांशियाग्रस्त सहचरी बन गई। यदि शब्दब्रह्म ही परमब्रह्म है तो भारतेन्दु हरिश्चंद्र के ब्रह्मन्तरी को प्रतिष्ठित करें:

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिनु रहत दीन के दीन।।

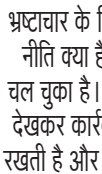
■ **घनश्याम सक्सेना**
(वरीष्ठ पत्रकार और संपादक)

ट्विटर



भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने आते ही इरादे साफ कर दिए थे। उन लोगों को सरकार सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है, जो अब तक बचे हुए थे।

जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री



भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति क्या है, यह सभी को पता चल चुका है। मोदी सरकार चेहरा देखकर कार्रवाई करने में यकीन रखती है और बातें खूब करती है।

मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता



सत्यार्थ

कई सुख-सुविधाओं के बावजूद इंसान कहीं-न-कहीं बेचैन है। सब कुछ मिल गया, तो भी वह खुश नहीं रह पाता। कभी उसे अपने सहकर्म के प्रमोशन से दुख होता है, तो कभी पड़ोसी के यहां नया सामान आ जाने से। लेखक डेल करनेगी की मांनें, तो पैसे की गरीबी इतनी दुखदायी नहीं है, जितनी प्रगति के लिए आकुलता की कमी। कारनेगी अपनी किताब 'द लीडर इन यू' में लिखते हैं कि इंसान को मानव बनाने वाले गुण हैं-सहजता, सरलता, सादगी और स्वीकारता। सहजता यानी जो जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार



हमें उसकी जरूरत होती है। जरूरत खत्म, तो स्वीकार्यता खत्म। इससे हमारा जीवन तनावों से

कर लेना। स्थान, समय व वातावरण के अनुसार ढल जाना ही सादगी है। स्वीकार्यता- जो सबको स्वीकार करता है, उसे भी सब लोग स्वीकार करते हैं। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, हम इन मौलिक गुणों से दूर होने लगते हैं। सहजता के स्थान पर दिखावा व आडंबर हावी होने लगता है। हमें लगता है कि एकमात्र हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। हम किसी को उतने ही समय तक स्वीकार करते हैं, जितने समय तक कसौटी खोजनी होगी। सवाल हमारी भावी पीढ़ी का है। बोलचाल की हिन्दी में अंग्रेजी सहित अन्य

भर जाता है। न हम व्यक्तिगत जीवन में सही रह पाते हैं और न ही व्यावहारिक जीवन में। इस संदर्भ में विद्वान लॉयड शीयरर कहते हैं कि हमें अपनी आम जिंदगी में छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमजोर एवं गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आना चाहिए। हम सभी कभी-न-कभी इनमें से किसी स्थिति से गुजरते हैं। यही हकीकत हमारे इंसान होने की आकांक्षा है। प्रत्येक संवेदनशील चाहता है कि वह समृद्ध या संपन्न होने से पहले एक बेहतर और अच्छा इंसान बने। दुनिया में आने का सही अर्थ भी तो यही है।

■ **शशिप्राभा तिवारी**

न्यूज

बड़े भाई के खिलाफ याचिका वापस लेंगे शिविंदर

नई दिल्ली। फौंटिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि वह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी में अपने बड़े भाई मालीवंदर सिंह तथा रेलिंगेयर के पूर्व प्रमुख सुनील गोधवानी के खिलाफ याचिका वापस लेने जा रहे हैं। शिविंदर ने इस बारे में एनसीएलटी में आवेदन किया है। शिविंदर ने इससे पहले आपाप लगाया था कि उनके बड़े भाई तथा गोधवानी की गतिविधियों की वजह से कंपनियों तथा उनके शेयरधारकों का हित प्रभावित हुआ है। शिविंदर मोहन सिंह ने कहा, मैंने एनसीएलटी में याचिका वापस लेने के लिए आवेदन कर दिया है। मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि इससे बात नहीं बनती है तो मेरे पास अपील दौबारा दायर करने का विकल्प होगा।

गणेश चतुर्थी पर बंद रहे शेयर और मुद्रा बाजार

मुंबई। गणेश चतुर्थी के मौके पर गुरुवार को शेयर तथा मुद्रा बाजार बंद रहे।कारोबारियों ने बताया कि गुरुवार को अवकाश का दिन होने के कारण शेयर बाजारों के किसी भी लेटफॉर्म पर कोई कारोबार नहीं हुआ। इसके साथ मुद्रा बाजार भी बंद रहा। कारोबारियों के अनुसार, शुक्रवार से बाजार में सामान्य कारोबार होगा।

बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए के खिलाफ एक्शन तेज

नई दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए से छुटकारा पाने पर एक्शन तेज कर दिया है। बैंक ने 8 हजार 831 करोड़ रुपए के 45 एनपीए बेचने के लिए बोली मंगाई है। आपको बता दें कि कल एसबीआई और आंध्र बैंक ने भी बड़े एनपीए के लिए बोली मंगाई थी। यानि सरकारी बैंक एनपीए से निपटारे के लिए हरकत में आ गए हैं।

चौथे प्लांट के लिए जमीन की तलाश में मारुति

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी भारत में अपने चौथे प्लांट के लिए जमीन तलाश रही है। कंपनी ने हरियाणा सरकार से नए प्लांट के लिए जमीन मांगी है। मारुति सुजुकी की गुरुग्राम प्लांट से मैनुफैक्चरिंग नए प्लांट में शिफ्ट करने की तैयारी है। इसके लिए सोहना में 1200 एफड जमीन के लिए कंपनी ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है।

बाजार समीक्षा

अगस्त के दौरान सोना आयात बढ़कर करीब 100 टन

स्वर्ण आभूषण निर्यात दोगुना बढ़ा



की बढ़त दर्ज करा गया। उक्त अवधि के दौरान भारत से रत्नाभूषणों का निर्यात में कमी दर्ज हुई है। अप्रैल से जुलाई के दौरान रत्नाभूषण निर्यात 10.638 अरब डॉलर मूल्य का हुआ, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 11.126 अरब डॉलर का हुआ था। भारत में गत अगस्त माह के दौरान सोने का आयात 100 टन पर पहुंच गया, जो कि मई 2017 के बाद किसी भी एक माह में होने वाला सबसे अधिक आयात था। जुलाई में 68 टन व जून में 59 टन सोना आयात हुआ था।

पॉलिसीबाजार ने लॉन्च किया कैशलेस वलेम फीचर

गुरुग्राम। इश्योरेटैक ब्रांड और भारत की सबसे बड़ी इश्योरेन्स वेबसाइट एफ कम्येरिजन पोर्टल पॉलिसीबाजार डॉटकॉम ने वलेम की आसान एवं जल्दी प्रोसेसिंग और सेटलमेंट के लिए अपने ऐप पर सेल्फ-वीडियो कैशलेस वलेम फीचर का नया वर्जन लॉन्च किया है। पब्लिक सेक्टर इश्योरर, न्यू इंडिया अश्योरेंस एवं युनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स ने सबसे पहले इस नए फीचर को अपनाया है और उपभोक्ताओं को एक्सीडेंटल वलेम के लिए सेटलमेंट सुविधाएं प्रालब्ध कराने पॉलिसीबाजार डॉटकॉम के साथ हाथ मिलाए हैं। याशील दहिया, सह-स्थापक एवं सीईओ, पॉलिसीबाजार ग्रुप ने कहा, हम अपने संगठन में उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उपभोक्ताओं को बीमा सेवाओं का बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए हमने नए पीबी वलेम फीचर लॉन्च किया है। इस ऐप से अनुमोदन, नॉन-रिपेयर टाईमलाईन दो दिनों से कम होकर मात्र दो घंटे हो जाएगी।

सिएट आयुष्मान ट्रैक्टर मीट नें फैलाई जागरुकता

नई दिल्ली। टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड ने अशोक नगर में किसान समुदाय के लिए जागरुकता शिविर आयुष्मान ट्रैक्टर मीट का आयोजन किया। यह ट्रैक्टर मीट बहुत सफल रही और किसान किसानों ने इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में टायर से संबंधित उन समस्याओं और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने का मौका मिला, जो भारत में किसान समुदाय के सामने आती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की लाभदेयता बढ़ाने में काम आने वाले सिएट के आयुष्मान टायर रेंज का प्रदर्शन भी किया गया। सिएट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग नीतीश बजाज ने कहा, किसानों को टायरों की उम्र बढ़ाने के तरीके और नुस्खे समझाने के लिए आयुष्मान ट्रैक्टर मीट जैसे जागरुकता कार्यक्रम जरूरी हैं। इससे हमें पंचवर से सुरक्षित और मजबूत पकड़ वाले सिएट आयुष्मान टायरों की रेंज दिखाने का मौका भी मिला है।

कैबिनेट नोट जल्द ही तैयार होने की उम्मीद



नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय इस्पात के स्कैपेज को लेकर एक नीति बना रही है, जिसका कैबिनेट नोट जल्द ही तैयार होने की उम्मीद है। इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस्पात के पुराने उत्पादों की स्कैपेज नीति पर कैबिनेट नोट जल्द तैयार कर लिया जायेगा और मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की वाहन स्कैपेज नीति का इंतजार किये बिना अपनी अलग नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुराने वाहनों को स्कैप करने से ही 70 लाख टन इस्पात बनाया जा सकता है। इसमें 40 प्रतिशत उत्तर भारत में उपलब्ध होगा जिससे उत्तर भारत में भी इस्पात उद्योग विकसित हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत में खनिजों की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में धातु उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। इस्पात सचिव विनय कुमार ने बताया कि यूरोपीय संघ द्वारा इस्पात के आयात पर 25 प्रतिशत अस्थायी सीमा शुल्क लगाये जाने के मुद्दे पर सरकार वहां के अधिकारियों से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यात से यूरोप का इस्पात उद्योग प्रभावित नहीं होगा क्योंकि यहां से होने वाला निर्यात काफी कम है। इसलिए, हमने उनसे भारतीय इस्पात को सीमा शुल्क से बाहर रखने का अनुरोध किया है।

धीमी पड़ी ग्रोथ की रफ्तार

नई दिल्ली। जुलाई में ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आई है। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 6.6 फीसदी रही है जबकि जून में आईआईपी ग्रोथ सात फीसदी के स्तर पर रही थी। महीने दर महीने आधार पर जुलाई में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 6.9 फीसदी से बढ़कर सात फीसदी रही है। महीने दर महीने आधार पर जुलाई में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 6.6 फीसदी से घटकर 3.7 फीसदी रही है। महीने दर महीने आधार पर जुलाई में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ 8.5 फीसदी से घटकर 6.7 फीसदी रही है।

महीने दर महीने आधार पर जुलाई में कैपिटल गुड्स की ग्रोथ 9.6 फीसदी से घटकर तीन फीसदी रही है। महीने दर महीने आधार पर जुलाई में प्राइमरी गुड्स की ग्रोथ 9.3 फीसदी से घटकर 6.9 फीसदी रही है। महीने दर महीने आधार पर अप्रैल में कंज्यूम ड्युरेबल्स गुड्स की ग्रोथ 13.1 फीसदी से बढ़कर 14.4 फीसदी रही है।

जुलाई में आईआईपी वृद्धि दर 6.6 फीसदी पर

कोकिंग कोल पर आयात शुल्क घटाने को लेकर बातचीत जारी

श्री सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ ही यूरोपीय संघ में निर्यात को लेकर आ रही समस्याओं से भी सरकार अलगत है तथा वह इन्हें दूर करने के उपाय कर रही है। इसके अलावा क्षेत्र के लिए कम दर पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी वह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कोकिंग कोल पर आयात शुल्क घटाकर शून्य करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ बात चल रही है। उल्लेखनीय है कि इस्पात उद्योग में कोकिंग कोल का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। इस कोयले के लिए भारत मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। अभी इसके आयात पर 2.5 प्रतिशत आयात शुल्क है।

इस्पात पर अमेरिकी शुल्क भारत के लिए चिंता का कारण नहीं : सरकार

सरकार ने कहा कि इस्पात आयात शुल्क में अमेरिका द्वारा की गयी बढ़ोतरी फिलहाल भारत के लिए चिंता का कारण नहीं है, हालांकि देश में इस्पात की डीपिंग रोकने के लिए वह पूरे उपाय करेगी। इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यहां द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करने के बाद कहा, हमारे इस्पात निर्यात का मात्र 0.31 प्रतिशत अमेरिका को जाता है और इसलिए अमेरिका द्वारा सोना शुल्क बढ़ाने का कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय में इस्पात निर्यात में मामूली गिरावट जरूर आयी है, लेकिन फिलहाल यह चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि अन्य देश उनके यहां से अमरीका को होने वाले सात से साढ़े सात करोड़ टन इस्पात को दूसरी जगह डंप करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक डीपिंग को लेकर कोई चिंता की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन यदि भविष्य में ऐसा होता है तो सरकार इसे रोकने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी।

इस्पात उद्योग के नवाचार अग्रदूत होंगे पुरस्कृत

नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय ने इस उद्योग में अच्छा नवाचार करने वालों को पुरस्कृत करने की घोषणा की तथा प्रस्ताव किया है कि इस्पात क्षेत्र से पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा के साथ नाम भेजे जाने चाहिये। इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यहां वर्ष 2016-17 के द्वितीयक इस्पात उद्योग पुरस्कारों के वितरण के बाद कहा कि इस्पात उद्योग में किसी भी पेटेंटड नवाचार या अनुसंधान के लिए पुरस्कार की स्थापना की जायेगी। उन्होंने इसके लिए नवाचार अग्रदूत पुरस्कार नाम का सुझाव दिया है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए दूसरे पुरस्कारों के लिए अक्टूबर में नाम आमंत्रित किया जायेगे। गुरुवार को 12 कंपनियों को गोल्ड श्रेणी में और 14 को सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों को प्रशस्ति पत्र दिये गये। श्री सिंह ने सुझाव दिया कि खेल की तरह ही इस्पात क्षेत्र से भी यदि किसी का नाम पद्म पुरस्कारों के लिए भेजा जाता है तो मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिये ताकि मंत्रालय उस पर अपनी अनुशंसा दे सके।

स्पीड में रिलायंस जियो सातवें महीने अत्तल

नई दिल्ली। देश के दूरसंचार क्षेत्र में महज दो वर्ष पहले पदार्पण करने वाली रिलायंस जियो के नये कीर्तिमान बनाने का सिलसिला जारी है। कंपनी स्पीड टेस्ट में इस क्षेत्र की अन्य कंपनियों को काफी पीछे छोड़ते हुए जुलाई में 22.3 एमबीपीएस औसत 4जी डाउनलोड स्पीड के साथ लगातार सातवें माह अत्तल रही है। दूरसंचार नियामक ट्राई के गुरुवार को प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार जुलाई में अन्य कंपनियों इस मामले में रिलायंस जियो की तुलना में बहुत पीछे रही। जियो के 22.3 एमबीपीएस 4जी डाउनलोड स्पीड की तुलना में दूसरांचर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरटेल 10 एमबीपीएस 4जी डाउनलोड स्पीड के साथ दूसरे स्थान पर रही। वोडाफोन 6.7 एमबीपीएस के सातवां तीसरे और आईडिया 6.2 एमबीपीएस के साथ चौथे स्थान पर रही।

आईटी और फार्मा में आएगी नौकरियों की बहार

नई दिल्ली। आने वाले दिनों में इन दो सेक्टरर्स में बंपर नौकरियां निकलने वाली हैं। आईटी सेक्टर में जोरदार हायरिंग शुरू हो चुकी है तो फार्मा ग्रेजुएट्स को एक रौबदार नौकरी करने का मौका मिलने वाला है। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि दोनों ही सेक्टर में नौकरियों के शानदार मौके आ रहे हैं।

आईटी सेक्टर में वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में 24000 नौकरियां मिलने की उम्मीद है। जबकि वित्त वर्ष 2018 में इस सेक्टर में सिर्फ 13000 नौकरियां मिली थीं। अगले तीन साल में इस सेक्टर में नौकरियों के अवसर और बढ़ेंगे। टीसीएस, कांनिजेंट, एचसीएल, एफसिस, विप्रो में नौकरियों अच्छे



मौके हैं। टीसीएस को 5.6 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वहीं, विप्रो के पास 1.6 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। आगे आईटी ग्रेजुएट्स के लिए आउटसोर्सिंग के काम की भरमार रहने की संभावना है। डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए आईटी वेंडर्स की जरूरत बढ़ रही है।

कंपनी कानून में संशोधन हुए प्रभावी

नई दिल्ली। सरकार ने कंपनी कानून, 2013 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है और इसके साथ ही कंपनी संशोधन कानून, 2017 के जरिये किये गये पांच संशोधन प्रभावी हो गये हैं। कंपनी कानून, 2013 की पांच धाराओं 196, 197, 198, 200 और 201 को संशोधित किया गया है। अब ये सभी संशोधित धारायें प्रभावी हो गयी हैं। इसके प्रभावी होने के साथ ही अब कंपनियों को अपने प्रबंधकीय कमियों के सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। कार्याधिकारियों और गैर-कार्यकारी निदेशकों को निर्धारित सीमा से अधिक का भुगतान करने के लिए अब एक विशेष प्रस्ताव के जरिये श्रेयधारकों की अनुमति लेनी होगी। सरकार ने कहा है कि इससे कंपनी के श्रेयधारक सशक्त होंगे और कंपनियों के कामकाज में सरकारी नीतियों का दखल कम होगा।

स्किलिंग से रोजगार के साथ आर्थिक विकास को मदद मिलेगी

कारोबार को करना पड़ रहा विरोधाभास का सामना

नई दिल्ली। केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को कहा कि स्किलिंग से न सिर्फ अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के लिए दक्ष बनाया जा सकेगा बल्कि इससे आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। श्री प्रभु ने 14वें इंद्रो यूएस आर्थिक शिखर सम्मेलन में भारतीय श्रमबल की स्किलिंग का उल्लेख करते हुये कहा कि देश के कारोबार को अभी बहुत ही

विरोधाभास का सामना कर रहा है।

एक तरफ बहुत से युवा रोजगार की तलाश में हैं जबकि दूसरी ओर उद्योग एवं कारोबारी कहते हैं कि वे दक्ष लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस अंतर को पाटने के लिए भारत में स्किल आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा। उन्होंने स्किलिंग को अर्थव्यवस्था में तेजी लाने वाला बताते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में स्किलिंग पर अधिक ध्यान दिये जाने का अपना मूल्य और आर्थिक संभावनाएं हैं।

मुंग दाल एवरेज	5900-6000	मुंबई	895
मुंग दाल बोलड	6100-6200	मुंबरात लूज	850-860
मुंग मोगर पॉलिखड	6100-6200	राजकोट तेलिया टिन	1370-1380
मुंग मोगर बोलड	6400-6600	रिल्वन	(प्रति विक्टल)
उड़द दाल चालू	4650-4750	सोयाबीन नया	3000-3200
उड़द दाल बोलड	4850-4950	सोयाबीन जून	3150-3325
उड़द मोगर	5400-5700	सोयाबीन प्लांट डिले.	3350-3400
दलहन	(प्रति विक्टल)	सरसोई कंडीशनर आयातित	4375-4400
चना	4125-4150	रायडा	3700-3800
विशाल चना	4025-4050	तेल टिन	
डॉलर चना	4000-5600	वनस्पति तेल	1000-1020
मसूर	3740-3750	मुंगफली तेल	1400-1525
तुवर सफेद	3900-3950	समस्तावर तेल	1380-1400
तुवर लोकल	3300-3600	सोयाबीन तेल	1150-1250
उड़द बोलड	3700-3800	सरसो तेल	1400-1500
उड़द पर्वज	3000-3500	खोपरा तेल	3000-3150
मुंग बेस्ट	4600-5000	कपारया खली	(प्रति 60 किलो) देव अन्न
मुंग एवरेज	4000-4400	इंदौर	1500
बटरी	0000-0000	देवास-ऊजैन	1500-1505
तेल-रिल्वन	(प्रति 10 किलो)	खंडवा-दुर्गामपुर	1490-1495
सोयाबीन रिफाईंड	743-745	अकोला (प्रति विक्टल)	1900
सोया सॉलेंट	705-710	मया	(प्रति किलो)
मुंबई सोया रिफाईंड	740	इंदौर	220
सोया डिगम		ऊजैन	152
708		रालाम	170-190
पाम तेल मुंबई	678-680	आटा-मैदा-बेरुन	(प्रति 50 किलो)
पाम तेल इंदौर	725	अटा-कड़ा	1150-1160
कापारया तेल	750-760	मैदा कड़ा	1220-1225 रु।
मुंगफली तेल इंदौर	870-890		

केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ का नया इन्वेस्ट 4जी प्लान लॉन्च

नई दिल्ली। जीवन बीमा क्षेत्र की कंपनी केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस ने नया यूनित लिंक्ड प्लान इन्वेस्ट 4जी लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को यहां जारी बयान में कहा कि यह प्लान ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुसार उपयुक्त संरक्षण का चयन करने के लिए एक विस्तृत विकल्प प्रदान करता है। इसको नये डिजिटल दौर के ग्राहकों की जरूरतों को हिसाब से डिजाइन किया गया है। उसने कहा कि पॉलिसी परिपक्वता पर मॉर्टेनैटिटी चार्ज की वापसी जैसी सुविधाओं के साथ यह एक प्रतिस्पर्धी उत्पाद है जो ग्राहकों को अपने बदलते जीवन स्तर की जरूरतों और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने में मददगार है। कंपनी ने इसे पॉलिसीबाजारडॉटकॉम के सहयोग से तैयार किया है। वह वेब एप्लीकेटोर्स और डिजिटल वितरण चैनलों के माध्यम से प्लान को बढ़ावा देगी।

रोजर दुबुई ने मोनाको में नया बुटिक खोला

मुंबई। रोजर दुबुई ने विश्व प्रसिद्ध रियासत मोनाको में एक नया स्टोर खोला है। विगत एक वर्ष से यह घड़ी निर्माता लेबोर्गिनी ड्रॅगनस् के साथ जुड़ा रहा, इसलिए यह एक मात्र फिटिंग थी कि ला रोचर-द रॉक को आशियाना बनाया जाए, यह एक प्रतिष्ठित एवं आलीशान स्थान है और कार उद्योग की जन्मस्थली भी है। भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह इसके भागीदार पिरेली के काफी नजदीक है, जो हर वर्ष शहर को अपने मोटरस्पोर्ट गतिविधियों से एक नया स्वरूप प्रदान करता है। यहां पर मुख्य टाइम्प्रीसेज और मोटरस्पोर्ट संग्रह एक्सकेलिबर एफेंडर एएसएस और एक्सकेलिबर स्पाइडर पिरेली को स्टोर खिड़कियों में प्रदर्शित किया गया है। बुटीक का एक वर्ग महिलाओं की घड़ियों को समर्पित होगा, जबकि बुकचेस में निर्मित लाल पृष्ठभूमि के साथ केस प्रदर्शित करते हैं और एस्टल दीवार उकृष्ट कृतियों और नए मॉडल आने पर उन्हें यहां प्रदर्शित किया जाएगा।

